12 रुपए

0506

मुख्यमंत्रियों का जनमत सर्वेक्षण ◆ कारोबारः नई कारों का जलवा

साथ में यूपी-उत्तरांचल की अंदरूनी खबरें

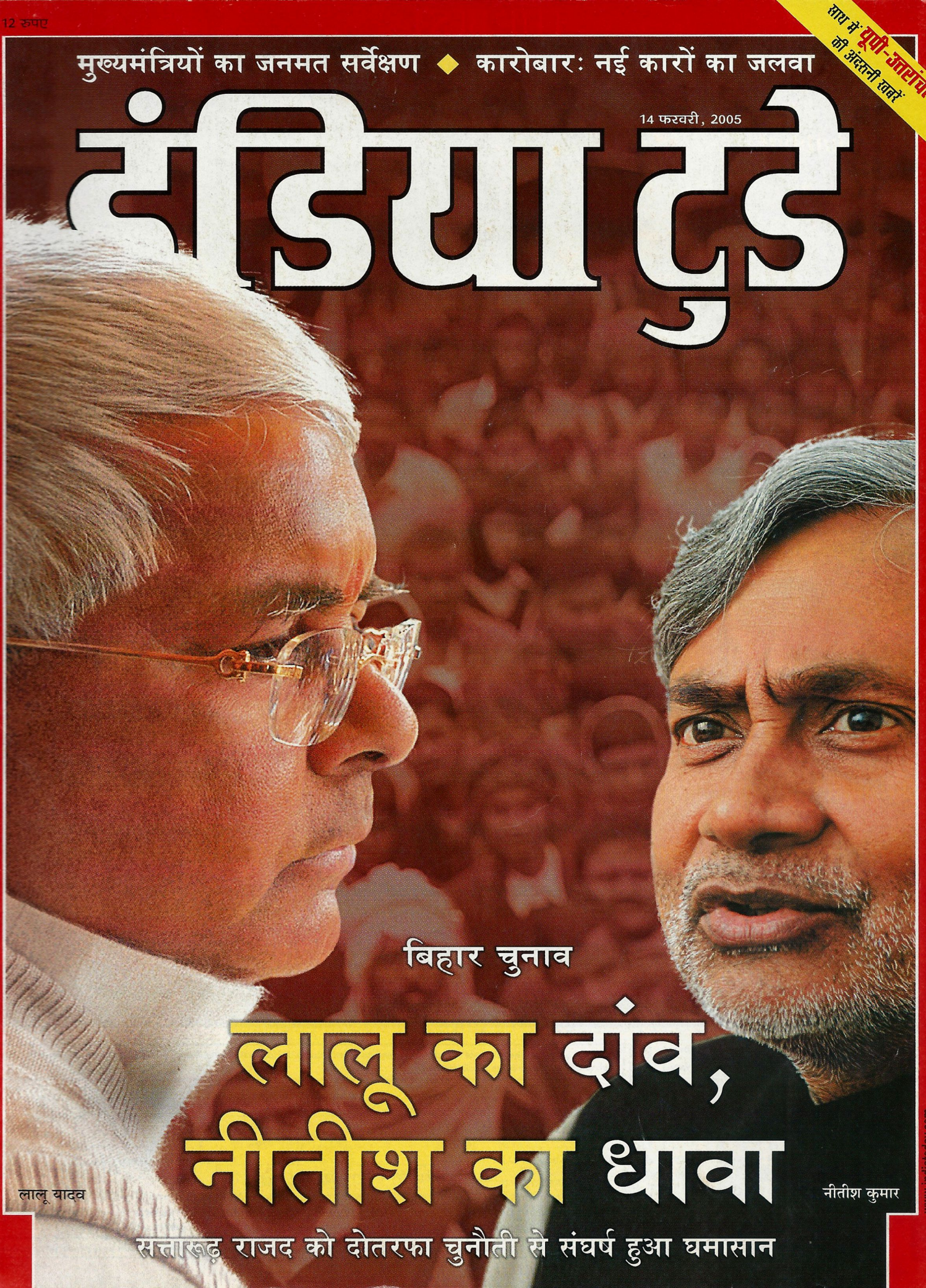

14 फरवरी, 2005

इंडिया टुडे

लालू यादव

नीतीश कुमार

बिहार चुनाव

लालू का दांव, नीतीश का धावा

सत्तारूढ़ राजद को दोतरफा चुनौती से संघर्ष हुआ घमासान

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPER FOR INDIA UNDER NO. 45828/86

www.indiatoday.com

रोशनी है जिनके दम से

कुछ अधिकारी अपने विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर, जन समस्याओं का समाधान करके साबित कर रहे हैं कि सरकार के स्तर पर मामूली पहल से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है

■ सुभाष मिश्र

उन्हें देश में सफेद हाथियों की फौज कहा जाता है और आम धारणा है कि सरकार मानो उन्हें काम रोकने के लिए ही नियुक्त करती है. राजनैतिक आकाओं की चाटुकारिता, भ्रष्टाचार और जातिवाद से उत्तर प्रदेश में अफसरशाही की छवि लगातार दागदार हो रही है. तकरीबन सौ वरिष्ठ अफसरों पर सतर्कता विभाग की जांच चल रही है और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ अधिकारी हैं जो न केवल अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते हैं बल्कि अपनी ओर से सकारात्मक पहल भी करते हैं हालांकि ऐसे अधिकारियों की तादाद लगातार घट रही है.

उत्तर प्रदेश के प्रदेशीय औद्योगिक विकास निगम (पिकअप) के प्रबंध निदेशक अनिल स्वरूप ऐसे ही अधिकारियों में से एक हैं. उन्होंने इस प्रतिष्ठित निगम को मौत के मुंह से खींच लिया है. 1972 में गठन के बाद पिकअप ने 1,108 औद्योगिक इकाइयों में 1,432 करोड़ रु. का निवेश किया, जिससे 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलीं. मगर समय के साथ यह निगम भ्रष्टाचारी नेताओं और अफसरशाहों का स्वर्ग बन गया. निगम का सकल घाटा 500 करोड़ रु. से ज्यादा हो गया.

पिछले दो साल से पिकअप ने कर्ज देने का अपना मुख्य काम बंद कर दिया और उसे मृत संगठन माना जाने लगा. इसी दौरान मुख्य सचिव वी.के. मित्तल ने खुद रुचि लेकर अनिल स्वरूप को निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया. स्वरूप कहते हैं, ''सबसे पहले मैंने फिजूलखर्ची रोकने के उपाए अपनाने का फैसला न सिर्फ पैसा बचाने के लिए, बल्कि निगम के कर्मियों में लक्ष्य हासिल करने का जज्बा जगाने के लिए भी किया.'' स्वरूप खुद आधिकारिक बैठकों के लिए बेहद जरूरी न होने पर विमान से नहीं जाते और ट्रेन के वातानुकूलित तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते हैं. खर्चों में और कटौती करने के लिए उन्होंने सुरक्षा के मद में होने वाले खर्च में काफी कमी की. उन्होंने व्यवस्था की कि निगम की देखरेख और सुरक्षा के अधीन चलने वाली उन इकाइयों की सुरक्षा में कटौती की जाए, जिन पर बकाया है. निगम बकाएदार औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा पर एक करोड़ रु. से ज्यादा खर्च कर रहा था मगर पिछले सात महीनों से इस खर्च में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आई है. स्वरूप बताते हैं, ''निगम अपने कर्मचारियों को सालाना 6.5 प्रतिशत ब्याज

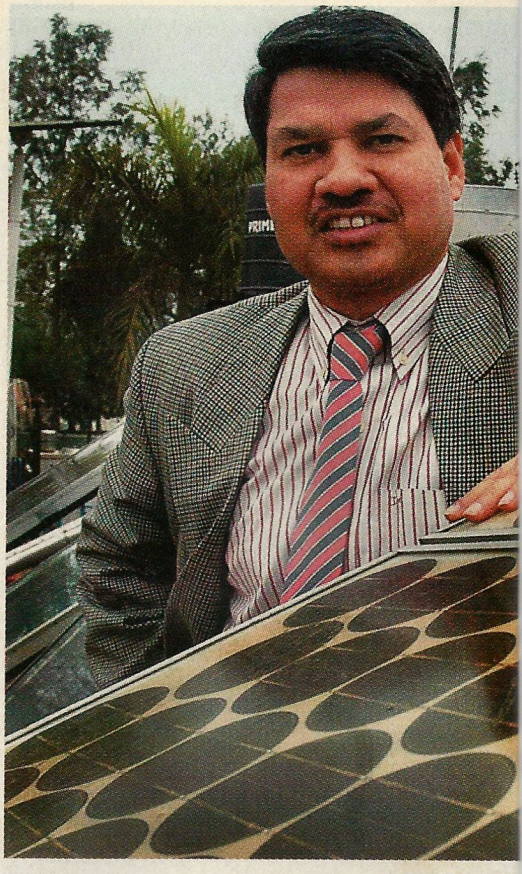

आमोद कुमार

जिलाधीश, सीतापुर, के लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए खास पहल की.

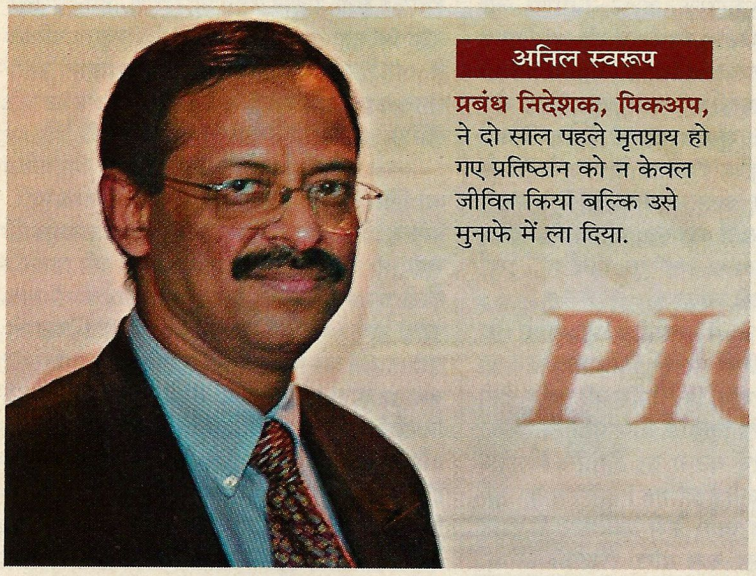

अनिल स्वरूप

प्रबंध निदेशक, पिकअप, ने दो साल पहले मृतप्राय हो गए प्रतिष्ठान को न केवल जीवित किया बल्कि उसे मुनाफे में ला दिया.

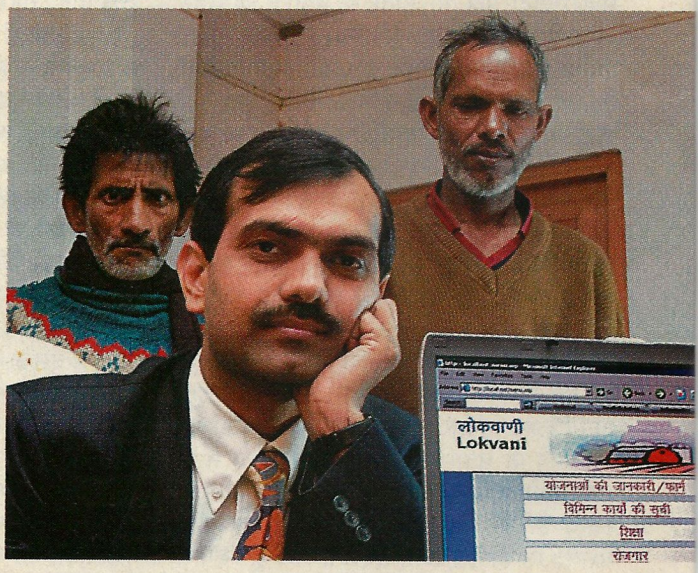

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

जी.बी. पटनायक

प्रमुख सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा चालित उपकरणों को लोकप्रिय बनाकर पहली बार राज्य में अपने विभाग की मौजूदगी का एहसास कराया.

दर पर आवास ऋण दे रहा था जबकि उसे बाजार से 12-13 प्रतिशत की दर से कर्ज लेना पड़ता था. अब सभी कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेने पर राजी हो गए हैं.''

इधर, पिकअप को पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में अपने कर्जों की उगाही का जिम्मा सौंपा. नतीजा यह निकला कि 11 साल बाद पिकअप ने मुनाफा दर्ज किया. इस तरह स्वरूप के 'ऑपरेशन पिकअप' से निगम की सेहत सुधरने लगी है, इसलिए पहली दफा राज्य सरकार ने उसमें जान फूंकने के लिए पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है.

स्वरूप से पहले पिकअप को सुधारने का प्रयास वी.एन. गर्ग ने किया था, जो हाल तक उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड के आयुक्त रहे हैं. उन्होंने बकाएदारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए थे. लेकिन इस काबिल प्रशासक ने पिछले हफ्ते तक कार्यकाल में बोर्ड में क्रांतिकारी बदलाव कर दिए. यह रिश्वतखोरी का पर्याय बना हुआ था लेकिन उन्होंने न सिर्फ बोर्ड को जनहितैषी बनाया, बल्कि लोगों की जरूरतों के अनुसार घर बनाए, सस्ते मकानों की शुरुआत की और आइआइएम-लखनऊ की मदद से बोर्ड की कामकाज की शैली भी बदली. गर्ग कहते हैं, ''शिकायतों का निवारण महज तीन दिनों में कर दिया जाता है.'' इसके पहले निवारण की कौन कहे, शिकायतें ही कूड़ेदान में फेंक दी जाती थीं. पहली दफा किसी सरकारी उपक्रम को आइएसओ सर्टिफिकेट जारी किया गया.

अपने हलके में 'वीएन' के नाम से मशहूर गर्ग एक सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं जिन्हें अपने काम की कीमत भी अदा करनी पड़ी है. उन्होंने सत्ता से करीबी रसूख रखने वाले बिल्डर अंसल्स की आवास विकास बोर्ड की जमीन अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया. उनके राजनैतिक आका इससे इस कदर खीझ गए कि एक ताकतवर मंत्री ने उन्हें अंसल की कॉलोनी मंजूर करने या अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. इसके फौरन बाद गर्ग बोर्ड के आयुक्त पद से हटा दिए गए और उन्हें उनकी वरिष्ठता के मुकाबले कनिष्ठ पद पर भेज दिया गया. वैसे, गर्ग सिर्फ इतना कहते हैं, ''मैं लोगों की सेवा करने के लिए हूं, पद मेरे लिए मायने नहीं रखता.''

वैसे, जिला स्तर के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी गर्ग के उलट होते हैं. वे अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं और लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते. इसी के मद्देनजर सीतापुर के जिलाधीश आमोद कुमार अपने जिले में लोगों की शिकायतों को तेजी से दूर करने के लिए नए-नए उपाए अपनाते हैं. उन्होंने *जनवाणी* कार्यक्रम शुरू किया है और हिंदी में एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है. वे कहते हैं, ''हमने तहसीलों में कंप्यूटर की गुमटियां लगाई हैं, जहां गांववाले अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उचित समय के भीतर उनका समधान करा सकते हैं.'' इससे लोगों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसा कि आमोद कहते हैं, ''मैं स्वयं अपने मुख्य कंप्यूटर में हर शिकायत को देखता हूं और उसके सामाधान पर नजर रखता हूं'' *जनवाणी* कार्यक्रम पांच अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी पर अंकुश लगेगा.

लेकिन जहां बिजली ही न हो वहां कंप्यूटर कैसे काम करेगा और इसके जरिए जिलाधीश को शिकायत करना तो दूर की बात है. राज्य भारी बिजली संकट से भी जूझ रहा है और निकट भविष्य में बिजली की कमी 3,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी. राज्य में अक्षय ऊर्जा विभाग (नेडा) के प्रमुख सचिव जी.बी. पटनायक कहते हैं, ''सोनभद्र जिला अधिकतम ताप बिजली उत्पादन के मामले में राज्य की ऊर्जा राजधानी जैसा है मगर जिले में बिना बिजली वाले गांवों की संख्या सबसे अधिक है.''

ऐसे में पटनायक ने राज्य के ग्रामीणों के साथ-साथ शहरी इलाकों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने का मन बनाया. वे बताते हैं, ''सौर ऊर्जा की अकूत संभावनाओं के चलते मैंने लोगों से सौर ऊर्जा का

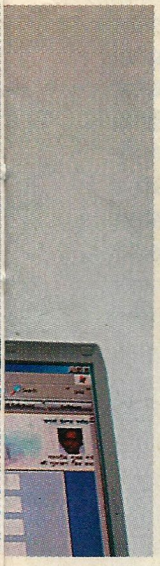

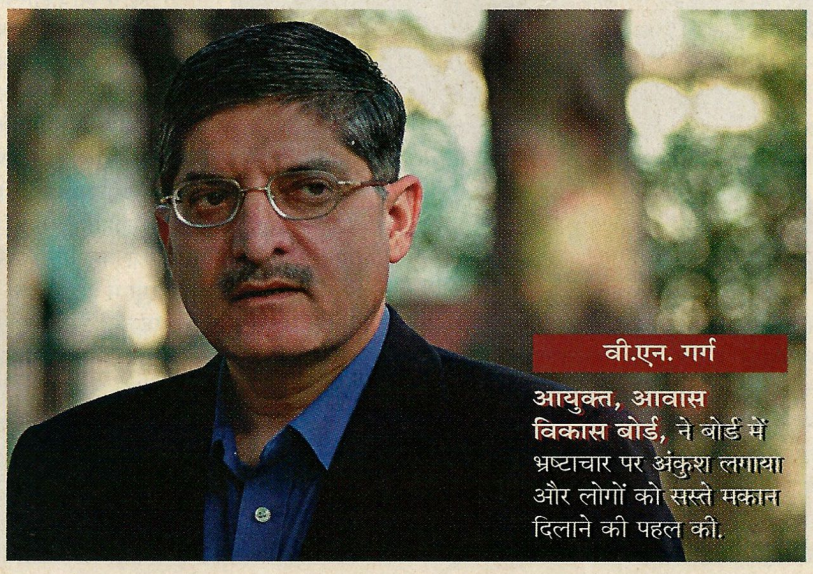

वी.एन. गर्ग

आयुक्त, आवास विकास बोर्ड, ने बोर्ड में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और लोगों को सस्ते मकान दिलाने की पहल की.

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

जी.बी. पटनायक

प्रमुख सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा चालित उपकरणों को लोकप्रिय बनाकर पहली बार राज्य में अपने विभाग की मौजूदगी का एहसास कराया.

दर पर आवास ऋण दे रहा था जबकि उसे बाजार से 12-13 प्रतिशत की दर से कर्ज लेना पड़ता था. अब सभी कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेने पर राजी हो गए हैं.''

इधर, पिकअप को पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में अपने कर्जों की उगाही का जिम्मा सौंपा. नतीजा यह निकला कि 11 साल बाद पिकअप ने मुनाफा दर्ज किया. इस तरह स्वरूप के 'ऑपरेशन पिकअप' से निगम की सेहत सुधरने लगी है, इसलिए पहली दफा राज्य सरकार ने उसमें जान फूंकने के लिए पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है.

स्वरूप से पहले पिकअप को सुधारने का प्रयास वी.एन. गर्ग ने किया था, जो हाल तक उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड के आयुक्त रहे हैं. उन्होंने बकाएदारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए थे. लेकिन इस काबिल प्रशासक ने पिछले हफ्ते तक कार्यकाल में बोर्ड में क्रांतिकारी बदलाव कर दिए. यह रिश्वतखोरी का पर्याय बना हुआ था लेकिन उन्होंने न सिर्फ बोर्ड को जनहितैषी बनाया, बल्कि लोगों की जरूरतों के अनुसार घर बनाए, सस्ते मकानों की शुरुआत की और आइआइएम-लखनऊ की मदद से बोर्ड की कामकाज की शैली भी बदली. गर्ग कहते हैं, ''शिकायतों का निवारण महज तीन दिनों में कर दिया जाता है.'' इसके पहले निवारण की कौन कहे, शिकायतें ही कूड़ेदान में फेंक दी जाती थीं. पहली दफा किसी सरकारी उपक्रम को आइएसओ सर्टिफिकेट जारी किया गया.

अपने हलके में 'वीएन' के नाम से मशहूर गर्ग एक सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं जिन्हें अपने काम की कीमत भी अदा करनी पड़ी है. उन्होंने सत्ता से करीबी रसूख रखने वाले बिल्डर अंसल्स की आवास विकास बोर्ड की जमीन अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया. उनके राजनैतिक आका इससे इस कदर खीझ गए कि एक ताकतवर मंत्री ने उन्हें अंसल की कॉलोनी मंजूर करने या अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. इसके फौरन बाद गर्ग बोर्ड के आयुक्त पद से हटा दिए गए और उन्हें उनकी वरिष्ठता के मुकाबले कनिष्ठ पद पर भेज दिया गया. वैसे, गर्ग सिर्फ इतना कहते हैं, ''मैं लोगों की सेवा करने के लिए हूं, पद मेरे लिए मायने नहीं रखता.''

वैसे, जिला स्तर के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी गर्ग के उलट होते हैं. वे अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं और लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते. इसी के मद्देनजर सीतापुर के जिलाधीश आमोद कुमार अपने जिले में लोगों की शिकायतों को तेजी से दूर करने के लिए नए-नए उपाए अपनाते हैं. उन्होंने *जनवाणी* कार्यक्रम शुरू किया है और हिंदी में एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है. वे कहते हैं, ''हमने तहसीलों में कंप्यूटर की गुमटियां लगाई हैं, जहां गांववाले अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उचित समय के भीतर उनका समधान करा सकते हैं.'' इससे लोगों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसा कि आमोद कहते हैं, ''मैं स्वयं अपने मुख्य कंप्यूटर में हर शिकायत को देखता हूं और उसके सामाधान पर नजर रखता हूं'' *जनवाणी* कार्यक्रम पांच अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी पर अंकुश लगेगा.

लेकिन जहां बिजली ही न हो वहां कंप्यूटर कैसे काम करेगा और इसके जरिए जिलाधीश को शिकायत करना तो दूर की बात है. राज्य भारी बिजली संकट से भी जूझ रहा है और निकट भविष्य में बिजली की कमी 3,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी. राज्य में अक्षय ऊर्जा विभाग (नेडा) के प्रमुख सचिव जी.बी. पटनायक कहते हैं, ''सोनभद्र जिला अधिकतम ताप बिजली उत्पादन के मामले में राज्य की ऊर्जा राजधानी जैसा है मगर जिले में बिना बिजली वाले गांवों की संख्या सबसे अधिक है.''

ऐसे में पटनायक ने राज्य के ग्रामीणों के साथ-साथ शहरी इलाकों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने का मन बनाया. वे बताते हैं, ''सौर ऊर्जा की अकूत संभावनाओं के चलते मैंने लोगों से सौर ऊर्जा का

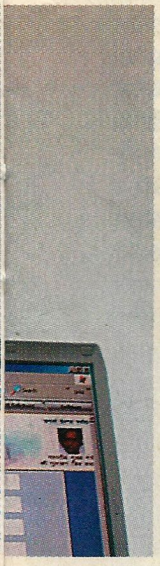

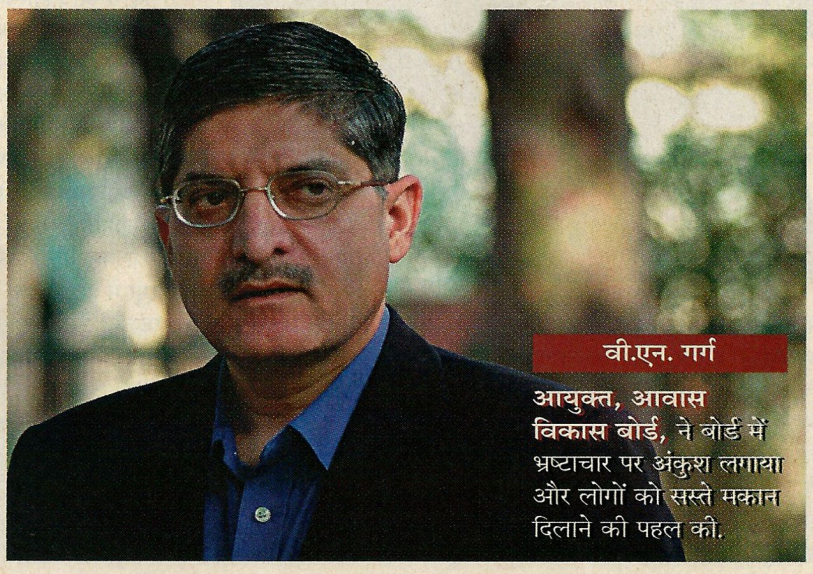

वी.एन. गर्ग

आयुक्त, आवास विकास बोर्ड, ने बोर्ड में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और लोगों को सस्ते मकान दिलाने की पहल की.